मई , 2024 , वर्ष : 45 अंक : 05

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

जीकग्याब रिनपोछे ने जापानी सांसदों से अपील की

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

मई , 2024 , वर्ष : 45 अंक : 05

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

सीटीए ने अमेरिकी सीनेट द्वारा तिब्बत समाधान विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने की सराहना की

प्रधान संपादक
ताशी देकि

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
मिग्मार छमचो

वितरण प्रबंधक
नावांग छोडेंन

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

- बुद्ध पूर्णिमा (वैशाखी) –२०२४ के अवसर पर परम पावन दलाई लामा का संदेश 1
- परम पावन दलाई लामा ने 'चिंतनशील साधना के प्रभाव की खोज' विषय पर आयोजित सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित किया 2
- २०वीं विश्व उग्यूर कांग्रेस की वर्षगांठ पर सिक्योंग ने चीन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सीसीपी के खिलाफ एकीकृत कार्रवाई का आह्वान किया 3
- सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने बोलजानो के राष्ट्रपति कोम्पत्शोर से मुलाकात की कोम्पत्शोर ने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति को उजागर करने के लिए संसदीय पहल का नेतृत्व करने का आश्वासन दिया 4
- सिक्योंग ने जर्मनी में तिब्बती अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में बात की, यूरोप से अधिनायकवादी चीनी शासन के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया 5
- भारत-तिब्बत सहयोग मंच के रजत जयंती समारोह में शामिल हुईं कालोन ग्यारी डोल्मा 6
- सीटीए ने अमेरिकी सीनेट द्वारा तिब्बत समाधान विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने की सराहना की 7
- केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने राष्ट्रपति पदक से नवाजे जाने पर स्पीकर एमेरिटस नैन्सी पेलोसी को बधाई दी 8
- प्रतिनिधि जेनखांग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने स्पेनिश संसद में तिब्बत पर चर्चा की 9
- ११वें पंचेन लामा के जबरन अपहरण किए जाने की २९वीं बरसी पर डीआईआईआर का बयान 10

समाचार -

- पंचेन लामा को मुक्त कराने के लिए विनियस स्थित चीनी दूतावास के समक्ष तिब्बत समर्थक समूह द्वारा शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन 11
- निर्वासित तिब्बती संसद पहुंचे सांसद शशि थरूर 12
- ज़ीकग्याब रिनपोछे ने जापानी सांसदों से अपील की 13
- चीन समर्थक कार्यकर्ताओं ने शी जिनपिंग की हंगरी यात्रा के दौरान तिब्बती प्रदर्शनकारियों को परेशान किया 14
- एक्सक्लूसिव: मठ छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद किशोर तिब्बती भिक्षु ने आत्महत्या कर ली 15
- फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से चीनी राष्ट्रपति शी के साथ बातचीत में तिब्बत का मुद्दा फ्रांसीसी रणनीति के केंद्र में रखने का आग्रह 16
- चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में तिब्बत में मानवाधिकारों के निरंतर उल्लंघन का जिक्र 17
- तिब्बत के १४वें दलाई लामा होने के मायने 18
- अमेरिकी आयोग ने चीन द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म तेज 'चीनीकरण' पर प्रकाश डाला 19

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा
नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट

coordinator@indiatibet.net

अपनी बात

◆ मध्यममार्ग नीति अपनाने हेतु चीन पर बढ़ता दबाव

`बैसाख पूर्णिमा अर्थात् बुद्ध पूर्णिमा। मई, 2024 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भव्य-दिव्य आयोजन विभिन्न देषों में हुए। भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा को लुंबिनी में हुआ था। उन्हें बैसाख पूर्णिमा को बोधगया में ज्ञान-प्राप्ति हुई थी। उनका महापरिनिर्वाण बैसाख पूर्णिमा को ही कुषीनगर में हुआ था। जन्म, ज्ञान एवं निर्वाण की एक ही तिथि बैसाख पूर्णिमा। यही कारण है कि बौद्ध दर्षन में बैसाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसीलिये इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेष के कांगड़ा जिलान्तर्गत धर्मषाला के विषेष कार्यक्रम में परमपावन दलाईलामा ने अहिंसा, करुणा, दया एवं शांति के महत्व को अच्छी तरह स्पष्ट किया। बौद्ध धर्मगुरु दलाईलामा ने कहा कि ये मानवीय मूल्य हैं। ये सबके लिये आवष्यक हैं। सभी रिलिजन (पंथ, संप्रदाय, मजहब) के अनुयायियों के लिये तथा जो किसी भी रिलिजन को नहीं मानते, उनके लिये भी मानवीय मूल्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

दलाईलामा ने अपने अन्य आध्यात्मिक प्रवचन में भी बौद्ध ग्रंथों में वर्णित मानवीय मूल्यों की आवष्यकता पर जोर दिया। धर्मषाला स्थित अपने मंदिर में आध्यात्मिक पूजा-प्रार्थना के बाद प्रवचन करते हुए उन्होंने प्राचीन नालंदा परंपरा की व्याख्या की तथा बताया कि बौद्ध चिंतन-मनन पर आधारित इसी नालंदा परंपरा ने भारत को जगत् गुरु बनाया था। प्राचीन नालंदा परंपरा में संचित ज्ञान-विज्ञान का भंडार हमेषा समाज का मार्गदर्षन करता रहेगा। प्रसन्नता की बात है कि दलाईलामा स्वयम् विष्वभर में इस ज्ञान-भंडार का गौरवगान करते रहते हैं। इस आधार पर उन्हें भारत की प्राचीन नालंदा परंपरा का वास्तविक उत्तराधिकारी कहना गलत नहीं होगा।

इसी मई, 2024 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित तिब्बत की निर्वासित सरकार के सिक्योंग (राजप्रमुख) माननीय पेंपा त्सेरिंग ने यूरोपीय देषों का प्रवास किया। वे चाहते हैं कि वर्ष 2009 से रूकी तिब्बत-चीन वार्ता पुनः प्रारम्भ हो। वार्ता का आधार "मध्यममार्ग" हो। इस नीति के अनुसार अपने संविधान एवं राष्ट्रीयता संबंधी कानून के अनुरूप चीन सरकार तिब्बत को "वास्तविक स्वायत्तता" प्रदान करे। विदेष तथा प्रतिरक्षा विभाग चीन सरकार के पास हों। कृषि, षिक्षा आदि अन्य विषय तिब्बत सरकार को मिलें। भारत से संचालित निर्वासित तिब्बत सरकार तिब्बत की "पूर्ण आजादी" की जगह सिर्फ "वास्तविक स्वायत्तता" लेने को तैयार है। इस प्रस्ताव को मान लेने पर चीन की भौगोलिक एकता-अखंडता-संप्रभुता के साथ ही तिब्बतियों के "स्वषासन" के अधिकार का भी संरक्षण हो जायेगा।
स्वतंत्र तिब्बत पर अवैध नियंत्रण के बाद चीन ने तिब्बत को तथाकथित स्वयत्तता प्रदान की है। स्वयत्तता के नाम पर उसने तिब्बत के भौगोलिक क्षेत्र में फेरबदल कर बड़े हिस्से को

चीन का भूभाग बना लिया है। सम्पूर्ण तिब्बत क्षेत्र का चीनीकरण, तिब्बती नामों में बदलाव तथा मानवाधिकारों के हनन से तिब्बत में तिब्बती पहचान संकटग्रस्त है।

सिक्योंग पेंपा त्सेरिंग ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी में सप्रमाण बताया कि तिब्बत में क्रूरतापूर्ण चीनी नीति लगातार जारी है। उन देषों में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे- जनप्रतिनिधि, प्रषासक, युवा, पत्रकार, षिक्षाविद् आदि से उन्होंने अपील की कि वे तिब्बती प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता पुनः प्रारम्भ करने के लिये चीन सरकार पर दबाव डालें। परिणामतः फ्रांस में तिब्बत संबंधी सर्वदलीय संसदीय समूह ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से आह्वान किया है कि चीन के साथ फ्रांस की द्विपक्षीय वार्ता में वे तिब्बत समस्या तथा इसके समाधान हेतु "मध्यममार्ग नीति" को गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत करें। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी में क्रियाषील तिब्बत संबंधी सर्वदलीय संसदीय समूह भी अपनी सरकारों से ऐसी ही अपील कर रहे हैं। ये सभी संसदीय समूह अपनी सरकारों से मांग कर रहे हैं कि अमरीकी सरकार की तरह उनके देषों में भी तिब्बत समस्या के समाधान हेतु अधिनियम बनाये जायें।

अमरीकी जनप्रतिनिधि सभा ने नवंबर, 2023 में पूर्ण बहुमत से तिब्बत समस्या के हल हेतु विधेयक पारित किया था। अभी मई, 2024 में अमरीकी सिनेट ने भी सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया है। अब अमरीकी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही अमरीकी कांग्रेस द्वारा पारित यह विधेयक अधिनियम हो जायेगा। इसके प्रावधानों के अनुरूप अमरीकी सरकार द्वारा चीन के साथ वार्ता में तिब्बत के सवाल को प्रमुखता से उठाया जायेगा तथा मध्यममार्ग नीति को अपनाकर तिब्बत को "वास्तविक स्वायत्तता" देने की मांग की जायेगी।

तिब्बत समर्थक अन्य सभी देषों को भी चीन के साथ अपनी द्विपद्वक्षीय वार्ता में अमरीकी सरकार की तरह दृढ़ता दिखानी होगी। अपने राष्ट्रीय हित में भारत सरकार भी तिब्बती आंदोलन में निर्णायक साथ दे। भारत की "शांति-सुरक्षा-समृद्धि-स्वाभिमान" की दृष्टि से ऐसा करना आवष्यक है।

अवैध चीनी आधिपत्य होने तक तिब्बत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की थी। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने उस समय अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह स्वतंत्र तिब्बत देष को साम्यवादी चीन का अभिन्न क्षेत्र मान लिया। उस समय अनेक भारतीय राजनेताओं ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी थी कि वे चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करें। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत के तिब्बत संबंधी गलत निर्णय के कारण चीनी विस्तारवाद का अगला षिकार भारत होगा। उनकी आषंका सन् 1962 में सही साबित हुई क्योंकि चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन लगातार भारत विरोधी नीति पर चल रहा है। चीन से भारत के संबंध सुधारने हेतु तिब्बत समस्या का हल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त है।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◆ 1.बुद्ध पूर्णिमा (वैशाखी) –२०२४ के अवसर पर परम पावन दलाई लामा का संदेश

dalailama.com,०९ मई, २०२४

धर्मशाला। परम पावन दलाई लामा ने तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने, साका दावा के शुभ महीने कीशुरुआत पर भक्तों और अनुयायियों को एक संदेश दिया, जिसमें उन्हें 'आनंद और करुणा से भरा सार्थक जीवन' जीने के लिए प्रेरित किया।

परम पावन ने संदेश में लिखा, 'बुद्ध को भारत में पैदा हुए और उपदेश दिए हुए २५०० साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन उनके उपदेशों का सार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। एक ओर जहां आधुनिक विज्ञान ने भौतिक दुनिया की एक परिष्कृत समझ विकसित की है, वहीं बौद्ध विज्ञान ने मन और भावनाओं के कई पहलुओं की एक विस्तृत, मौलिक समझ विकसित करने में अपनी सारी ऊर्जा को लगाया है। बौद्ध विज्ञान आधुनिक विज्ञान के लिए अभी भी अपेक्षाकृत अबूझ और अगम हैं। मेरा मानना है कि इन दो दृष्टिकोणों के संमिश्रण से ऐसे नए आविष्कारों के आने की बहुत संभावना है, जो हमारे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को समृद्ध करेंगे।

तिब्बती बौद्ध भिक्षु के रूप में मैं खुद को नालंदा परंपरा का उत्तराधिकारी मानता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरह से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और जिस तरह से वहां अध्ययन-अध्यापन किया जाता था, वह भारत में इसके विकास के चरम को दर्शाता है। अगर हमें २१वीं सदी का

बौद्ध बनना है तो यह महत्वपूर्ण है कि केवल आस्था पर निर्भर रहने के बजाय हम बुद्ध के प्रवचनों के अध्ययन और विश्लेषण में संलग्न हों। ऐसा बहुत से लोगों ने किया भी है। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाखी पूर्णिमा शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण का स्मरण करता है। इस तिथि को बौद्ध कैलेंडर में सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी बौद्धों को परमानंद और करुणा से भरे सार्थक जीवन जीने की शुभकामनाएं देता हूं।

प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के साथ।

◆ 2.परम पावन दलाई लामा ने 'चिंतनशील साधना के प्रभाव की खोज' विषय पर आयोजित सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित किया

dalailama.com,२४ मई, २०२४

थेकचेन चोलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत, २४ मई २०२४। आज २४ मई की सुबह परम पावन दलाई लामा ने एमोरी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध संस्थानों से आए लगभग २०० शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात की। ये लोग 'चिंतनशील साधना के प्रभाव की खोज' विषय परआयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए धर्मशाला आए हुए हैं। एमोरी कम्पैशन सेंटर के कार्यकारी निदेशक गेशे लोबसांग तेनजिन नेगी ने इस कार्यक्रम का परिचय दिया।

उन्होंने परम पावन से मुखातिब होते हुए अपने परिचयात्मक उद्बोधन की शुरुआत की, 'परम पावन, एमोरी विश्वविद्यालय और दलाई लामा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में हमें आमंत्रित करने के लिए मैं यहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।'

हमारे बीच एमोरी विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, कर्मचारी और छात्र; एमोरी-तिब्बत साइंस इनिशिएटिव (ईटीएसआई) के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी; सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा (एसईई लर्निंग) कार्यक्रमों का पालन करने वाले तिब्बती शिक्षक और छात्र के साथ ही अन्य पर्यवेक्षक और प्रतिभागी भी उपस्थित हैं।'

हमारे बीच पहली बार यह हो रहा है कि आधुनिक विज्ञान का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाले तिब्बती मठवासी विद्वान अपनी साधना के

क्षेत्र में चिंतन और अपने शोध के आधार पर मिले अनुभवों के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है। यह लगभग २० साल पहले तिब्बती मठवासी शिक्षा केंद्रों में विज्ञान को स्थान दिलाने के आपके दूरदर्शी निर्णय का फल है। विज्ञान अब तिब्बती मठवासी शिक्षा का अभिन्न अंग बन गया है। इस शिक्षा के परिणामस्वरूप, भिक्षु और भिक्षुणियां वैज्ञानिक सोच के साथ आगे आ रही हैं।'

एमोरी विश्वविद्यालय के डीन डॉ॰ बारबरा क्राउथमर को कार्यक्रम का संचालन सौंपने से पहले मैं टेम्पलटन फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डेविड नासर और टेम्पलटन फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक जॉन कनिंघम का परिचय देना चाहूंगा। हम उनकी यहां पर उपस्थित होने और पिछले दस वर्षों से ईटीएसआई कार्यक्रम के लिए फाउंडेशन को समर्थन प्रदान करने को लेकर उनके आभारी हैं।' डॉ. नेगी ने बताया कि तिब्बती संस्कृति, बौद्ध दर्शन और बौद्ध मन के विज्ञान का अध्ययन करने वाले एमोरी के छात्र; ईटीएसआई के छात्र और तिब्बती स्कूली बच्चों में से प्रत्येक से एक-एक बच्चे परम पावन से प्रश्न पूछेंगे।

एमोरी विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. बारबरा क्राउथैमर ने परम पावन को उनकी दूरदर्शिता और करुणा के लिए धन्यवाद दिया। इस पर परम पावन ने उत्तर दिया, 'आज मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है। बौद्ध धर्म के अध्ययन से हमें मनोविज्ञान, मन और भावनाओं के कामकाज के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जब लोग धर्म के बारे में बात करते हैं, तो वे आम तौर पर आस्था की बात करते हैं। धर्म में दिए गए तथ्यों की जांच करने के तरीकों की बात नहीं करते। हालांकि नालंदा परंपरा आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देती है और जब मन के अध्ययन की बात आती है तो इसके विद्वान इस मुद्दे पर गहरा अध्ययन करते हैं।'

जब भारतीय आचार्य शांतरक्षित आठवीं शताब्दी में तिब्बत पहुंचे तो उन्होंने पहचाना कि तिब्बतियों में गहन विचार करने की क्षमता है। यह हमारे प्रति उनकी करुणा का एक पैमाना था। 'मैं धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के बारे में बात करना पसंद करता हूं। इसमें जो चीज महत्वपूर्ण है, वह यह है कि उन्हें कोई भी व्यक्ति चाहे वे धार्मिक हों या नहीं, अपना सकता है। इसमें अहम मुद्दा यह पता लगाना है कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए। बौद्धों को यह भी समझना होगा कि अनुष्ठानों का आयोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अहम यह है कि क्या इससे हम दूसरों को और खुद को मन की शांति प्रदान कर सकते हैं। और ऐसा करने का तरीका मन का उपयोग करना है।'

वैसे तो मठवासी पाठ्यक्रम में हम चार बौद्ध दार्शनिक स्कूलों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो यह बात करना अधिक व्यावहारिक है कि हमारा मन और हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं। यह जनहित की बात है। अगर हम दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे विश्राम किया जा सकता है और किस तरीके से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है।'

एमोरी विश्वविद्यालय के एक छात्र ने परम पावन से पूछा कि आज की दुनिया में उम्मीद को कैसे कायम रखा जाए। परम पावन ने उत्तर दिया, 'अक्सर हमारे मन में कई तरह की अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में आई अपेक्षाएं बुरी और अच्छी दोनों ही तरह की हो सकती हैं। हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा।

हमें यह परखना होगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। कभी-कभी हम समाधान की तलाश में धर्म की ओर रुख कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अपनी बुद्धि और तर्क करने की क्षमता का उपयोग करना अधिक कारगर साबित होता है।

उन्होंने आगे कहा, 'जब हम मठों में औपचारिक शास्त्रार्थ करते हैं तो परंपरा के अनुसार चुनौती देने वालों के लिए अपने दावों के समर्थन में शास्त्रों से उद्धरण प्रस्तुत करना होता है। शास्त्रों से उनकी बात साबित हो जाने पर बचाव पक्ष के विद्वान अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपनी टोपियां उतार देते हैं। लेकिन फिर जवाब देते हैं कि जो उद्धृत किया गया है वह तार्किक रूप से उचित नहीं है। इसकी बजाय, वे घोषणा करते हैं कि आलोचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।'

उन्होंने कहा,'किसी भी स्थिति की वास्तविकता का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक उत्कृष्ट उपकरण है। नालंदा परंपरा भी हमें सिखाती है कि शास्त्रों का सहारा लिए बिना कैसे विश्लेषण और जांच-परख की जाए।'

ईटीएसआई कार्यक्रम के एक भिक्षु ने पूछा कि विज्ञान का अध्ययन करने वाले भिक्षु समाज में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। परम पावन ने उत्तर दिया:- 'अध्ययन का उद्देश्य दूसरों की बेहतर सेवा करने में सक्षम होना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग कारण और तर्क के साथ करना चाहिए। बेशक हम पुस्तकों को पढ़ने से मन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम अपने मन की वैज्ञानिक तरीके से जांच-परख करेंगे तो हम और अधिक विस्तार और गहनता से सीखेंगे।'

यह देखते हुए कि परम पावन धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की सराहना को प्रोत्साहित करने के लिए उत्सुक हैं और उनका सार करुणा है, तिब्बती चिल्ड्रन विलेज (टीसीवी) की एक छात्रा ने पूछा कि करुणा की प्रकृति क्या है।

परम पावन ने उससे कहा, 'विभिन्न परंपराएं हमें अधिक विचारशील और शिष्ट बनना सिखाती हैं। लेकिन करुणा दूसरों के प्रति संवेदनशील चिंता

के संदर्भ में होती है। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता हमें समाज का मार्गदर्शन करने का साधन प्रदान करती है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हर कोई सौहार्दपूर्ण व्यवहार की सराहना करता है।'

इस अवसर पर ईटीएसआई द्वारा प्रकाशित दो विज्ञान पुस्तकें परम पावन को भेंट की गईं। आगंतुक प्रतिभागी गण अपने-अपने समूहों में परम पावन के चारों ओर एकत्रित हुए और तस्वीरें खिंचवाईं।

◆ 3. २०वीं विश्व उग्यूर कांग्रेस की वर्षगांठ पर सिक्योंग ने चीन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सीसीपी के खिलाफ एकीकृत कार्रवाई का आह्वान किया

tibet.net, ०६मई, २०२४

म्यूनिख। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने ०३ मई २०२४ को म्यूनिख में विश्व उग्यूर कांग्रेस की २०वीं वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह को अतिथि वक्ता के रूप में संबोधित किया।

सिक्योंग ने स्वतंत्रता और न्याय की खोज में तिब्बतियों और उइगरों के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसके समर्थक में विश्व उग्यूर कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष एरकिन अल्पटेकिन और परम पावन दलाई लामा के पूर्व विशेष दूत दिवंगत लोदी ग्यारी के बीच एक समिति बनाने के प्रयासों में ऐतिहासिक सहयोग को याद किया। इसके अलावा सिक्योंग ने साझा प्रयासों के लिए विश्व उग्यूर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रेबिया कदीर और वर्तमान अध्यक्ष डोलकुन ईसा के साथ काम करने के अवसर के लिए भी आभार व्यक्त किया। सहयोग की अनिवार्यता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सिक्योंग ने कहा, 'मैं उइगरों, मंगोलों, अब मंचू भी, तिब्बतियों, हांगकांगवासियों, चीन में लोकतंत्र समर्थक नेताओं और यदि आप चाहें तो ताइवान को भी शामिल कर सकते हैं, हम सभी कम्युनिस्ट चीन के क्रूर तूफान के खिलाफ एक ही नाव में सवार हैं।'

इसी सुर में तिब्बती नेता ने यूरोप और अन्य देशों से अपनी अपील दोहराई कि वे तिब्बतियों और उइगरों को सहानुभूति के बजाय चीनी कम्युनिस्ट सरकार के अत्याचारों और आक्रामकता का मुकाबला करने में अपना भागीदार समझें। कोई भी चीन में अराजकता नहीं चाहता क्योंकि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन में अराजकता के दुनिया भर में गंभीर परिणाम होंगे।

हालांकि, अगर हमें चीन में सकारात्मक बदलाव लाना है तो हमें आंतरिक और बाहरी दोनों ताकतों की जरूरत है। इसमें हम आंतरिक ताकतें हैं।'

अपना संबोधन समाप्त करने से पहले सिक्योंग ने कहा, 'क्या हम यूरोप में सभी उइगरों, तिब्बतियों, हांगकांगवासियों, मंगोलों, ताइवानियों और लोकतंत्र समर्थक चीनी नेताओं की एक बड़ी रैली आयोजित कर सकते हैं? यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ जुड़ने या नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं।'

◆ 4.सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने बोलजानो के राष्ट्रपति कोम्पत्शोर से मुलाकात की कोम्पत्शोर ने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति को उजागर करने के लिए संसदीय पहल का नेतृत्व करने का आश्वासन दिया

Tibet.net, ०४ मई, २०२४

बोलजानो। निर्वासित तिब्बत सरकार के सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने गुरुवार को दक्षिण टायरॉल के बोलजानो स्वायत्त प्रांत के राष्ट्रपति कोम्पत्शोर से मुलाकात की। सिक्योंग की यह बोलजानो स्वायत्त प्रांत की दूसरी आधिकारिक यात्रा थी। सिक्योंग ने पिछली बार अक्तूबर २०२१ में दक्षिण

टायरॉल की अपनी पहली औपचारिक यात्रा पर राष्ट्रपति कोम्पत्शोर से मुलाकातकी थी।

एक घंटे तक चली उनकी मुलाकात में तिब्बत की भयावह स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया। बातचीत में तिब्बती लोगों के राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों में आई काफी गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई। इस गिरावट के कारण तिब्बत दक्षिण सूडान और सीरिया के बाद पृथ्वी पर सबसे कम आजादी वाला देश बन गया है।

सिक्योंग ने तिब्बत में चीन के सरकारी औपनिवेशिक प्रणाली के आवासीय स्कूलों की भयावह वास्तविकता के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी। चीन की तिब्बती नस्ल के चीनी हान नस्ल में विलय करने की नीति के तहत इन आवासीय स्कूलों में दस लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों और उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जबरन अलग करके रखा गया है।

इन चुनौतियों के बावजूद सिक्योंग ने तिब्बती भावना की संवेदनशील प्रकृति पर प्रकाश डाला। दक्षिण टायरॉल में सफल स्वायत्तता मॉडल से प्रेरणा लेते हुए इस मॉडल को सिक्योंग ने मानवता के लिए एक गहरा योगदान और तिब्बती लोगों के लिए विशेष रूप से सार्थक माना।

सिक्योंग ने राष्ट्रपति कोम्पत्शोर को सीटीए द्वारा आयोजित आगामी कार्यक्रम के भाग के लिए धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का दौरा करने के लिए आमंत्रण भी दिया, जिसे राष्ट्रपति ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया।

सिक्योंग की विशिष्ट अपीलों का जवाब देते हुए राष्ट्रपति कोम्पत्शोर ने तिब्बत के अंदर बिगड़ती स्थिति को उजागर करने के लिए संसदीय पहल का नेतृत्व करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा, उन्होंने दक्षिण टायरॉल और तिब्बत के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसके प्रतीक के तौर पर राष्ट्रपति ने बोलजानो में नए प्रांतीय पुस्तकालय की योजना का अनावरण किया।

इस योजना से अल्पसंख्यकों और स्वायत्तता के संरक्षण के लिए पुस्तकालय के प्रलेखन केंद्र (आर्काइव) में तिब्बत और तिब्बती आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

बैठक में सिक्योंग के साथ प्रतिनिधि थिनले चुक्की और डॉ. गुथर कोलोग्ना भी थे। बोलजानो प्रवास के दौरान सिक्योंग के सम्मान में स्थानीय तिब्बतियों ने रात्रिभोज का आयोजन किया।

इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय तिब्बतियों से मुलाकात की। इस अवसर पर डॉ. गुंथर कोलोग्ना और तिब्बत के अन्य पुराने मित्र भी शामिल हुए। प्रतिष्ठित ईयूआरएसी अनुसंधान केंद्र में सिक्योंग ने स्थानीय शोधकर्ताओं के साथ बातचीत की।

इसमें आज की उथल-पुथल भरी दुनिया में सीटीए के मध्यम मार्ग दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर चर्चा हुई और मध्यम मार्ग के समर्थन में तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति के पक्ष में बातें हुईं। शोधकर्ताओं ने ईयूआरएसी और सीटीए के बीच सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। बाद में सिक्योंग ने ईयूआरएसी की संचार टीम और ओआरएफ ऑस्ट्रियन टीवी सहित तीन प्रमुख समाचार मीडिया संस्थानों को साक्षात्कार दिए।

◆ 5.सिक्योंग ने जर्मनी में तिब्बती अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में बात की, यूरोप से अधिनायकवादी चीनी शासन के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया

tibet.net, १० मई, २०२४

बर्लिन। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रमुख सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने बर्लिन में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की और उनमें दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया: पहला, तिब्बत में चीन के सरकारी औपनिवेशिक प्रणाली के आवासीय स्कूलों का मुद्दा और दूसरा तिब्बती धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ परम पावन दलाई लामा के उत्तराधिकार सहित अनूठे बौद्ध परंपराओं की सुरक्षा। इन दो मुद्दों पर अमेरिकी नीतियों का हवाला देते हुए सिक्योंग ने बर्लिन में नेताओं से इसी तरह के नीतियां और कानून बनाने पर विचार करने और बहुपक्षीय मंचों से चीनी सरकार को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया।

सिक्योंग की यात्रा कार्यक्रमों में एक प्रमुख आकर्षण ०७ मई को जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के तहत धार्मिक और आस्था की स्वतंत्रता के लिए संघीय सरकार के आयुक्त की इकाई के निदेशक एन्के ओपरमैन के साथ उनकी बैठक थी।

आयोग में एक घंटे की बैठक के दौरान ओपरमैन ने सिक्योंग को धर्म और आस्था की स्वतंत्रता की वैश्विक स्थिति पर जर्मनी की संघीय सरकार की तीसरी रिपोर्ट और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोग द्वारा की जाने वाली आगामी पहलों के बारे में जानकारी दी।

बदले में, सिक्योंग ने ११वें पंचेन लामा को जबरन अपहरण कर लिए जाने के खिलाफ बयान देने के लिए आयोग, विशेष रूप से आयुक्त फ्रैंक श्वाबे को धन्यवाद दिया। सिक्योंग ने श्वाबे से इस मुद्दे पर निरंतर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करते रहने का आग्रह किया और बीएमजेड से आह्वान किया कि वह समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म को विशुद्ध रूप से धार्मिक मामले के तौर पर स्वीकार करे। साथ ही इस मामले को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने जर्मन बुंडेस्टैग (संसद) के सदस्य माननीय रोडेरिच कीसेवेटर से मुलाकात की। कीसेवेटर सीडीयू/सीएसयू कॉकस के लिए विदेशी मामलों के प्रतिनिधि और संसदीय निरीक्षण पैनल के उपाध्यक्ष भी हैं। सिक्योंग ने चीन के अधिनायकवादी शासन का सामना करने में तिब्बतियों से सीखे जा सकने वाले व्यावहारिक सबकों पर चर्चा की। दोनों ने मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। माननीय सांसद ने परम पावन दलाई लामा के शांति और अहिंसा के संदेश की स्थायी प्रासंगिकता के साथ-साथ तिब्बती लोगों के रणनीतिक अहिंसक संघर्ष की सराहना की।

०५, ०६ और ०८ मई को सिक्योंग ने उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारियों और अपने मामलों से संबद्ध हस्तियों के साथ बंद कमरे में बातचीत और गोलमेज बैठकें कीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने टेबल मीडिया, आरबीबी रेडियो, डाइज़िट और फ्रैंकफर्टर अल्गमेइने ज़ितुंग सहित प्रमुख जर्मन मीडिया आउटलेट्स से बातचीत की और चीन को लेकर एक मजबूत यूरोपीय नीति की वकालत की।

०६ और ०८ मई को सिक्योंग ने क्रमशः बर्लिन में प्रमुख तिब्बत समर्थक संगठनों अर्थात् तिब्बत इनिशिएटिव ड्यूशलैंड और आईसीटी जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और तिब्बत में बिगड़ती स्थिति को लेकर अभियान चलाने लायक आगामी परियोजनाओं पर रणनीति बनाने पर विचार- विमर्श किया।

जर्मनी में सिक्योंग पेन्पा शेरिंग का संदेश व्यापक तौर पर यूरोप और विशेष रूप से जर्मनी के लिए था कि वह चीन से निपटने में अपनी ताकत का भरपूर उपयोग करें और अधिनायकवादी शासन का मुकाबला करने में तिब्बतियों से प्रेरणा लें। उन्होंने जर्मनी से एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में जर्मनी में पोषित मूल्यों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

◆ 6.भारत-तिब्बत सहयोग मंच के रजत जयंती समारोह में शामिल हुईं कालोन ग्यारी डोल्मा

tibet.net, ०७ मई, २०२४

नई दिल्ली। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सुरक्षा विभाग की कालोन (मंत्री) डोल्मा ग्यारी ने ०६ मई २०२४ को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत-तिब्बत सहयोग मंच (बीटीएसएम) के रजत जयंती समारोह के समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में तिब्बती और भारतीय समुदायों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही और लगभग २०० सदस्य तिब्बती मुद्दे का समर्थन करने के लिए एकत्र हुए।

उपस्थित लोगों में बीटीएसएम के संरक्षक श्री डॉ. इंद्रेश कुमार, कालोन डोल्मा ग्यारी, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक श्री रिनचेन खांडू खिरमे, बीटीएसएम के राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज गोयल, सीआरपीएफ के एडीजी श्री सरदार एस.एस. संधू शामिल रहे। निर्वासित तिब्बती संसद के पूर्व उपाध्यक्ष और भारत-तिब्बत सहयोग मंच के वरिष्ठ सलाहकार आचार्य येशी फुंटसोक और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. गीता सिंह ने अतिथि वक्ता के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
कलोन ग्यारी डोल्मा ने अपने भाषण में उपस्थित लोगों को यारलुंग राजवंश के प्रथम राजा द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत प्राचीन काल से भारत-तिब्बत संबंधों के सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने भारत और तिब्बत के बीच भाईचारे के अस्तित्व को दोहराते हुए इस तथ्य को उजागर किया कि तिब्बत में ९९% तिब्बती लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। उन्होने यह भी कहा कि तिब्बती भाषा का मूल संस्कृत भाषा में गहराई से निहित है।

सीटीए कालोन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जे से पहले अपने पूरे इतिहास में कभी भी चीन के साथ एक इंच भी सीमा साझा नहीं

किया। उन्होंने यहां आए लोगों से यह भी अपील की कि वे यहां से जाकर आम लोगों को भी इस तथ्य से अवगत कराएं। चीन द्वारा हाल में अरुणाचल प्रदेश के ३० और स्थानों का नाम बदलने के कृत्य के बारे में पूछे जाने पर सीटीए कालोन ने कहा, 'अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।' उन्होंने तिब्बती लोगों को शरण देने और समुदाय को अपना प्रशासन स्थापित करने देने के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया। सीटीए कालोन ने भारत सरकार से तिब्बत-चीन संघर्ष को लेकर अपनी पहले की अस्पष्ट नीति में बदलाव करने की भी अपील की।

सीआरपीएफ के एडीजी श्री सरदार एस.एस. संधू ने कार्यक्रम के दौरान अतीत में जाकर उन्नीसवीं सदी के मध्य में डोगरा-तिब्बती युद्ध का जिक्र किया और कहा कि तिब्बत पर अवैध कब्जे से पहले भारत ने कभी चीन के साथ सीमा साझा नहीं की थी।

बीटीएसएम के संरक्षक श्री डॉ. इंद्रेश कुमार ने भारत और तिब्बत के बीच एक दशक पुराने संबंधों के बारे में जानकारी देते हुए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने उपस्थित लोगों को यह भी आश्वस्त किया कि वे तिब्बत मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी अपील करेंगे।

कार्यक्रम में तिब्बत समर्थकों और तिब्बती क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों को तिब्बती मुद्दे के प्रति उनके अटूट समर्थन के लिए सम्मानित किया गया।

भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय ने उपस्थित सभी लोगों के बीच तिब्बत से संबंधित पुस्तकें और पत्रिकाएं वितरित कीं। कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। विद्वान वक्ताओं और साहसी उपस्थित लोगों के माध्यम से यह कार्यक्रम तिब्बत मुद्दे के लिए प्रेरणा और सहयोग का एक उल्लेखनीय संगम साबित हुआ।

◆ 7.सीटीए ने अमेरिकी सीनेट द्वारा तिब्बत समाधान विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने की सराहना की

tibet.net, २४ मई, २०२४

धर्मशाला। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) ने अमेरिकी सीनेट द्वारा विधेयक-१३८ को 'तिब्बत-चीन विवाद समाधान अधिनियम' शीर्षक से सर्वसम्मति से पारित किए जाने की सराहना की है। अमेरिकी सीनेट ने २३ मई २०२४ को दोनों सदनों और दोनों दलों के समर्थन वाले विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक को इंडियाना से रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग के साथ कांग्रेस-कार्यकारी आयोग के सह-अध्यक्ष ओरेगन से डेमोक्रेट सीनेटर जेफ मर्कले ने संयुक्त रूप से प्रायोजित किया था।

तिब्बत समाधान विधेयक (रिजॉल्व तिब्बत बिल) के नाम से जाना जाने वाला यह अधिनियम तिब्बत-चीन संघर्ष का समाधान करने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित तिब्बती नेताओं के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के सीधे संवाद की वकालत करने की अमेरिकी नीति की पुष्टि करता है। यह मानता है कि तिब्बत-चीन संघर्ष अभी भी अनसुलझा है और तिब्बत की कानूनी स्थिति को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार देखा किया जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त, इस कानून का उद्देश्य तिब्बत के बारे में चीनी सरकार के दुष्प्रचारों का मुकाबला करना है, जिसमें तिब्बत के इतिहास, संस्कृति, लोगों और संस्थानों के बारे में मनगढ़ंत कथानक शामिल हैं। इनमें परम पावन दलाई लामा का इतिहास भी शामिल है।

सीनेटर मर्कले ने कहा, 'दुनिया भर में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जिनमें तिब्बतियों के लिए अधिकार भी शामिल हैं। तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाला हमारा दोनों दलों और दोनों सदनों से पारित सर्वसम्मत अधिनियम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की चालों का सीधा जवाब है, जो तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों को रौंद रहा है। यह विधेयक पीआरसी और तिब्बत के बीच चल रहे विवाद के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देता है और तिब्बत और उसके इतिहास के बारे में पीआरसी के दुष्प्रचारों का मुकाबला करता है। अब यह सीनेट से पारित हो गया है और हम इसे राष्ट्रपति बिडेन की टेबल तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि तिब्बत के लोगों को भविष्य में अपनी जिम्मेदारी संभालने

का रास्ता साफ हो सके।'

सीनेटर यंग ने कहा, 'तिब्बत के प्रति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामकता उसके अपने स्वार्थ में है। इसमें बातचीत और यहां तक कि तिब्बत की परिभाषा भी सीसीपी की इच्छा पर निर्भर है। हमें तिब्बत को लेकर अमेरिकी नीति को पुनर्निर्धारित करना चाहिए और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली बातचीत और दलाई लामा के साथ सीसीपी की वार्ता फिर से शुरू कराने पर जोर देना चाहिए। सीनेट से इस कानून को पारित होना अमेरिका के इस संकल्प को दर्शाता है कि तिब्बत और अन्य जगहों पर सीसीपी की कब्जे वाली यथास्थिति स्वीकार्य नहीं है।'

सिक्योंग पेन्पा शेरिंग ने सीनेट द्वारा बिल पारित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'साका दावा के दिन बहुत ही शुभ हैं। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से तिब्बत समाधान विधेयक (रिजॉल्व तिब्बत बिल) को पारित कर दिया। यह एक अहम कदम है जो हमें इस विधेयक के अधिनियमन की दिशा में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाता है और हमें सही दिशा की ओर ले जाता है। विधेयक को लेकर अब तक की प्रगति सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इसे अकेले एक व्यक्ति या समूह द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। अपने सीमित मानवीय और वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने यह प्रदर्शित किया है कि एक साथ काम करके हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हम विशेष रूप से इस विधेयक के प्रायोजकों- सीनेटर जेफ मर्कले और सीनेटर टॉड यंग तथा इस विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सह-प्रायोजकों और विधेयक को समर्थन देने के लिए सीनेट के आभारी हैं।'

◆ 8.केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने राष्ट्रपति पदक से नवाजे जाने पर स्पीकर एमेरिटस नैन्सी पेलोसी को बधाई दी

tibet.net, ०६ मई, २०२४

धर्मशाला। लंबे समय से तिब्बत की समर्थक रहीं स्पीकर एमेरिटस नैन्सी पेलोसी को ०३ मई २०२४ को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ़ फ्रीडम' से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान 'अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों, सुरक्षा के साथ विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक, सार्वजनिक तथा निजी प्रयासों में उनके अनुकरणीय योगदान' के लिए दिया गया है।
नैन्सी पेलोसी कांग्रेस के निचले सदन- प्रतिनिधि सभा की पूर्व अध्यक्ष के साथ-साथ इस सदन की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं। उन्होंने सदन में अपने साढ़े तीन दशकों के दौरान कांग्रेस में तिब्बत मुद्दे को अथक रूप से आगे बढ़ाया है। उनके अटूट समर्थन ने उन्हें वैश्विक मंच पर तिब्बत के सबसे प्रभावशाली और प्रभावी सहयोगियों में से एक बना दिया है। शुक्रवार को १८ लोगों के साथ उन्हें भी 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से सम्मानित किए जाने के अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रवक्ता, अतिरिक्त सचिव तेनजिन लेक्षय ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, 'केंद्रीय तिब्बती प्रशासन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नेन्सी पेलोसी को प्रतिष्ठित 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई देता है।'

◆ 9.प्रतिनिधि जेनखांग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने स्पेनिश संसद में तिब्बत पर चर्चा की

tibet.net, १३ मई, २०२४

ब्रुसेल्स। स्पेन के ~~भूतपूर्व सांसदों के संघ के अध्यक्ष और महासचिव के निमंत्रण पर ब्रुसेल्स~~ स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिग्जिन जेनखांग और यूरोप स्थित तिब्बती सांसद थुप्टेन वांगचेन ने तिब्बत की गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार, १० मई २०२४ को स्पेनिश संसद का दौरा किया। उनके साथ आईसीटी के कार्यकारी निदेशक वांगपो टेथोंग भी थे।
इस यात्रा ने तिब्बतियों की दुर्दशा के बारे में जागरुकता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके अधिकारों के पक्ष में अभियान चलाने के महत्व को रेखांकित किया।
चर्चा के दौरान प्रतिनिधि जेनखांग ने मानवाधिकारों के सुनियोजित उल्लंघन और तिब्बती भाषा, धर्म और संस्कृति को चीन के अनुकूल करने के चीनी सरकार के सुनियोजित प्रयासों को रेखांकित किया। प्रतिनिधि ने तिब्बती लोगों की दृढ़ता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने मुद्दों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया। जबकि सांसद थुप्टेन वांगचेन और वांगपो टेथोंग ने तिब्बत में धर्म की स्वतंत्रता और सामान्य रूप से यूरोप में तिब्बत मुद्दे के पक्ष में अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। स्पेनिश संसद के पूर्व सदस्यों ने तिब्बती मुद्दे में गहरी रुचि दिखाते हुए रचनात्मक संवाद में शामिल होकर अपने विचार रखे तथा तिब्बती लोगों के साथ उनके स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति अपनी चिंता और एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने तिब्बत की स्थिति के बारे में जागरुकता बढ़ाने के महत्व को स्वीकार किया और इस तरह की किसी भी पहल का समर्थन करने का वचन दिया।
कुल मिलाकर, प्रतिनिधि की स्पेनिश संसद की यात्रा भविष्य के सहयोग की नींव रखने वाली एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है।
यह कार्यक्रम तिब्बत के एक अच्छे मित्र पूर्व सीनेटर रॉबर्ट नाहर के प्रयासों से संभव हुआ।

◆ 10.११वें पंचेन लामा के जबरन अपहरण किए जाने की २९वीं बरसी पर डीआईआईआर का बयान

tibet.net, १७ मई, २०२४

२९ साल बीते : अब तक 'लापता'

पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के अधिकारियों ने आज से ठीक २९ साल पहले १९९५ में आज ही के दिन ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा का अपहरण कर लिया था। उस समय पंचेन लामा मात्र छह साल के बच्चे थे और तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धार्मिक नेताओं में से एक थे। १४ मई १९९५ को परम पावन १४वें दलाई लामा ने सार्वजनिक रूप से इस बच्चे को ११वें पंचेन लामा के रूप में चिह्नित किया था और आधिकारिक तौर पर उसे 'जेट्सन तेनज़िन गेधुन येशी ल्हिनले फुंटसोक पाल सांगपो' नाम दिया था। तीन दिन बाद ही १७ मई को युवा पंचेन लामा अपने माता-पिता और पंचेन लामा की सीट ताशी ल्हुनपो मठ के मठाधीश चाद्रेल रिनपोछे के साथ 'लापता' हो गए। पंचेन लामा के पुनर्जन्म को परम पावन दलाई लामा द्वारा मान्यता दिए जाने को नकारते हुए चीनी अधिकारियों ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके स्थान पर इस पीठ पर एक अन्य बच्चे को थोप दिया। २९ साल बाद आज भी पंचेन लामा, उनके माता-पिता और चाद्रेल रिनपोछे 'लापता' हैं और उनकी कोई खबर किसी को नहीं है।

इन वर्षों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विभिन्न सरकारों, संगठनों, समर्थकों और दुनिया भर के तिब्बतियों ने ११वें पंचेन लामा का पता लगाने के लिए कई स्रोतों से व्यापक प्रयास किए हैं। पंचेन लामा का मूल नाम गेधुन चोएक्यी न्यिमा है। कुछ लोगों ने तो कई मौकों पर संयुक्त राष्ट्र में तथा चीनी प्रतिनिधिमंडलों के साथ सीधे तौर पर पंचेन लामा के स्वास्थ्य और ठिकाने के बारे में चिंता जताई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के प्रवक्ता और सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के अतिरिक्त सचिव तेनजिन लेक्षय कहते हैं, 'हम चीन द्वारा ११वें पंचेन लामा को लंबे समय से जबरन गायब किए जाने की निंदा करते हैं और पीआरसी सरकार से २९ वर्षों से कैद किए गए पंचेन लामा को तुरंत रिहा करने की अपनी मांग दोहराते हैं। पीआरसी सरकार के अलावा और कहीं यह संभव नहीं हो सकता है कि एक वयस्क को दुनियादारी से पूरी तरह अनजान रखा जाए और उसे दुनिया से छिपा कर रखा जाए। अभी तक अपहृत पंचेन लामा के बारे में एक भी विश्वसनीय जानकारी या तस्वीर नहीं है। हम पीआरसी सरकार से मांग करते हैं कि वह पंचेन लामा, उनके माता-पिता और चाद्रेल रिनपोछे की कुशलता और उनके निवास स्थान की विश्वसनीय जानकारी सार्वजनिक करे। जब तक सत्य सामने नहीं आ जाता, हम उनकी आजादी की मांग करते रहेंगे।'

पिछले महीने २४ अप्रैल को पंचेन लामा ३५ साल के हो गए। सीटीए ने दुनिया भर के कई अन्य लोगों की तरह उनकी अनुपस्थिति में उनका जन्मदिन मनाया। जब तक पीआरसी उन्हें 'लापता' रखेगा, तब तक पंचेन लामा की रिहाई के लिए अभियान चलाने के सीटीए के प्रयास जारी रहेंगे, पंचेन लामा की खोज जारी रहेगी।

◆ 11.पंचेन लामा को मुक्त कराने के लिए विनियस स्थित चीनी दूतावास के समक्ष तिब्बत समर्थक समूह द्वारा शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन

Tibet.net, १९ मई, २०२४

लंदन। पंचेन लामा के अपहरण की २९वीं वर्षगांठ पर १७ मई को तिब्बत समर्थक समूह के सदस्यों ने विनियस स्थित चीनी दूतावास के समक्ष शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि लिथुआनियाई और यूरोपीय राजनेता तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन की समस्याओं पर ध्यान दें।

इस दिन १९९५ में छह वर्षीय गेधुन चोएक्यी न्यिमा का चीनी सरकार द्वारा अपहरण कर लिया गया और जबरन गायब कर दिया गया। तीन दिन पहले १४ मई १९९५ को ही उन्हें ११वें पंचेन लामा के अवतार के रूप में चिह्नित किया गया था। इस प्रदर्शन में तिब्बत समर्थक समूह के सदस्य रॉबर्ट्स माजेका ने जोर देकर कहा कि मान्यता प्राप्त पंचेन लामा के ठिकाने का खुलासा करने के लिए चीन पर दबाव डाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति को उजागर करने के लिए लिथुआनिया और अन्य देशों में तिब्बती समुदाय और उनके प्रतिनिधि यूरोपीय संसद के वर्तमान और भावी सदस्यों (एमईपी) से तिब्बत का समर्थन करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने का आह्वान कर रहे हैं।

तिब्बत हाउस के प्रमुख और विल्नियस विश्वविद्यालय में व्याख्याता व्यतिस व्यदुनास ने स्वीकार किया कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का प्रश्न लिथुआनियाई जनता को विचित्र लग सकता है, लेकिन यह वैश्विक महत्व का सांस्कृतिक पहलू है। श्री व्यदुनास ने कहा, 'तिब्बती हमारे स्वाभाविक सहयोगी हैं। उग्यूर

हमारे स्वाभाविक सहयोगी हैं, ठीक उसी तरह जैसे चीनी शासन रूस में वर्तमान में मौजूद तानाशाह और अमानवीय शासन का सहयोगी है। हमें तिब्बती संघर्ष का समर्थन करना चाहिए।'

तिब्बती और लिथुआनियाई झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांगों वाली तख्तियां लिए हुए थे। उन पर 'पंचेन लामा को मुक्त करो', 'तिब्बत में मानवाधिकारों का सम्मान करो', 'तिब्बतियों का सांस्कृतिक संहार बंद करो: औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल बंद करो!' जैसे बहुत सारे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने 'तिब्बत को आज़ाद करो' के नारे भी लगाए।

12.निर्वासित तिब्बती संसद पहुंचे सांसद शशि थरूर

tibet.net, ३० मई, २०२४

धर्मशाला। तिरुवनंतपुरम (केरल) से लोकसभा सांसद पूर्व केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर महासचिव डॉ. शशि थरूर ने ३० मई २०२४ को निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया। डॉ. थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन के नियोजित दौरे के बाद डिप्टी स्पीकर डोल्मा शेरिंग तेखांग के अलावा स्थायी समिति और लोक लेखा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की।

प्रतिनिधिमंडल ने ३० मई को सबसे पहले परम पावन दलाई लामा से मुलाकात की। निर्वासित तिब्बती संसद के निमंत्रण को प्राथमिकता पर लेते हुए थरूर द्वारा किए गए दौरे में टीपीआईई के सांसद यूडन औकात्सांग उनके साथ थे।

निर्वासित तिब्बती संसद में पहुंचने पर सांसद और उनके सहयोगियों का डिप्टी स्पीकर, स्थायी समिति और लोक लेखा समिति के सदस्यों और संसदीय सचिवालय के सचिव और वहां के कर्मचारियों ने स्वागत किया। डॉ. थरूर को संसद भवन का दौरा कराया गया, जिसके बाद स्थायी समिति के हॉल में बैठक हुई।

अपने स्वागत भाषण में डिप्टी स्पीकर ने तिब्बती मुद्दे के लिए डॉ. थरूर के स्थायी समर्थन, विशेष रूप से दिल्ली में अपने तिब्बती अभियान के दौरान निर्वासित तिब्बती संसद के प्रतिनिधिमंडलों से मिलने के लिए थरूर प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त किया।

डिप्टी स्पीकर ने २०२२ में वाशिंगटन डीसी में तिब्बत पर विश्व सांसदों के आठवें सम्मेलन में थरूर की बहुमूल्य उपस्थिति का हवाला देते हुए उसी जोश के साथ डॉ. थरूर से निरंतर समर्थन जारी रखने का आग्रह किया और तिब्बत पर विश्व सांसदों के आगामी नौवें सम्मेलन में भी उन्हें उपस्थित रहने का आग्रह किया।

भारत के विभिन्न राज्यों में तिब्बती संसद के पक्षधरता अभियान कार्यक्रम के बारे में प्रतिनिधिमंडल को जानकारी देते हुए डिप्टी स्पीकर ने पर्यावरण, राष्ट्रीय स्थिरता और जल संसाधनों के संदर्भ में तिब्बत के महत्व पर प्रकाश डाला।

डॉ. शशि थरूर ने तिब्बत और वहां के लोगों को भारत सरकार और उसके नागरिकों से मिले स्थायी समर्थन पर प्रकाश डाला, जो राजनीतिक संबद्धताओं से परे है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा के साथ अपनी मुलाकात को याद किया। उस दौरान परम पावन ने धार्मिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया, जबकि सांसद ने अपने प्रतिनिधिमंडल के भीतर विविधता को रेखांकित किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शामिल थे।

तिब्बत के पूरे इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए डॉ. थरूर ने १९५९ में परम पावन और तिब्बती शरणार्थियों के प्रति भारत के गर्मजोशी भरे स्वागत का उल्लेख किया, इस बात पर जोर देते हुए कि कैसे दलाई लामा ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रेम और करुणा के संदेशों का प्रसार किया है।

डॉ. शशि थरूर तिब्बत के समर्थक हैं और तिब्बत पर सांसदों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनपीएटी) के सदस्य भी हैं।

◆ 13.ज़ीकग्याब रिनपोछे ने जापानी सांसदों से अपील की

tibet.net, ०८ मई, २०२४

टोक्यो। परम पावन दलाई लामा के जापान और पूर्वी एशिया स्थित संपर्क कार्यालय ने ०७ मई २०२४ को टोक्यो में जापानी संसद के निचले सदन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में जापानी सांसदों के लिए तिब्बत कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में तिब्बत समर्थकों और मीडिया के लोगों ने भी भाग लिया। कार्यशाला का विषय था 'तिब्बत में मानवाधिकारों का उल्लंघन और धार्मिक अत्याचार'।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य इशिबाशी रिंटारो ने कार्यक्रम का संचालन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने सांसदों को पंचेन लामा मुद्दे पर जानकारी दी और बताया कि कैसे लगभग तीन दशक बाद भी उनका कोई अता-पता नहीं है।

परम पावन दलाई लामा के जापान और पूर्वी एशिया स्थित संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि डॉ. शावांग ग्याल्पो आर्य ने कार्यशाला में भाग लेने के लिए सांसदों, तिब्बत समर्थकों और मीडिया के सदस्यों को धन्यवाद

दिया। उन्होंने ज़ीकग्याब रिनपोछे का परिचय दिया और बताया कि कैसे तिब्बत में स्थिति खराब हो गई है और कैसे सीसीपी औपनिवेशिक प्रणाली के बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से तिब्बती पहचान और धार्मिक संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। तिब्बत में पुनर्जन्म लेने वाले सर्वोच्च लामाओं के चयन सहित अन्य धार्मिक मामलों में चीनी हस्तक्षेप जारी है।

दक्षिण भारत में ताशी ल्हुनपो मठ के मुख्य महंत ज़ीकग्याब रिनपोछे ने असली पंचेन लामा के गायब होने और तिब्बती धार्मिक मामलों में जारी चीनी हस्तक्षेप को लेकर अपने विचार रखे।

उन्होंने कहा, 'मैं तिब्बत की भयावह स्थिति के संदर्भ में यह हार्दिक अपील करता हूं। तिब्बती लोगों, उनके आंदोलन और उनकी स्वतंत्रता पर गंभीर उत्पीड़न और अमानवीय प्रतिबंध लगातार बदतर होते जा रहे हैं। तिब्बत के लोग चुपचाप पीड़ा को सह रहे हैं। आज मैं ११वें पंचेन लामा की तत्काल रिहाई और तिब्बती लोगों की मातृभूमि तिब्बत में लंबे समय से हो रही दुर्दशा को दूर करने में आपकी मदद के लिए है आपसे सर्बप्रथम अपील करता हूं।'

तिब्बत के प्रति सीसीपी की दमनकारी और औपनिवेशिक नीति पर बोलते हुए उन्होंने सांसदों और समर्थकों से तीन बिंदुओं पर अपील की-

१. जापानी संसद के सदस्य चीनी सरकार पर ११वें पंचेन लामा को तुरंत रिहा करने और उनके ठिकाने की घोषणा करने के लिए हरसंभव प्रयास करें और दबाव डालें।

२. तिब्बती धार्मिक मामलों में चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन और हस्तक्षेप की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करें, जिसमें परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म के चयन के मामले में चीनी हस्तक्षेप भी शामिल हो।

३. तिब्बत को शांति का क्षेत्र बनाने और बातचीत में मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के माध्यम से तिब्बत मुद्दे के समाधान में परम पावन दलाई लामा के दृष्टिकोण का समर्थन करें। लेखक विद्वान मिउरा जुन्को ने रिनपोछे के भाषण का अनुवाद किया।

चीन के मानवाधिकार उल्लंघन पर नजर रखने वाले जापानी सांसदों के समूह के अध्यक्ष कानूनविद फुरुया केइजी ने रिनपोछे को उनके बयान के लिए धन्यवाद दिया और तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता बहाली के अभियानों को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कानूनविदों से तीन बिंदुओं का अध्ययन करने और एक बयान जारी करने का आह्वान किया, जिसमें चीन से परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म के चयन में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया गया हो।

जापान पार्लियामेंटरी सपोर्ट ग्रुप फॉर तिब्बत के अध्यक्ष शिमोमुरा हकुबुन ने सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सद्भाव लाने में बौद्ध धर्म के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने जापानी संसद द्वारा तिब्बत और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन की निंदा करते हुए २०२२ में पारित प्रस्ताव की चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के दो सिक्योंग की जापान यात्रा और सांसदों के साथ उनकी बातचीत को याद किया।

श्रोताओं में मौजूद कानूनविदों ने तिब्बत की वर्तमान स्थिति, वहां की सूचनाओं और वहां के समाचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश किए जाने को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज़ीकग्याब रिनपोछे और डॉ. आर्य ने सांसद के सवाल का जवाब दिया और श्रोताओं को औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों, लारुंग गार और याचेन गार जैसे विश्व विख्यात बौद्ध मठों की स्थिति, ड्रैगो में बुद्ध की मूर्ति और प्रार्थना चक्रों के विनाश, १५८ तिब्बतियों के आत्मदाह और हाल में बांध निर्माण के लिए तिब्बतियों के जबरन विस्थापन के बारे में जानकारी दी।

कैबिनेट मामलों और डिजिटल मंत्रालय के उप मंत्री और 'जापान पार्लियामेंटरी सपोर्ट ग्रुप फॉर तिब्बत' के महासचिव सांसद इशिकावा अकिमासा ने ताशी ल्हुनपो मठ को लेकर चर्चा की। इस मठ के बारे में उन्होंने जापानी स्रोतों से पढ़ा कि कैसे मठ और पंचेन लामाओं ने तिब्बती धार्मिक संस्कृति की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

◆ 14.चीन समर्थक कार्यकर्ताओं ने शी जिनपिंग की हंगरी यात्रा के दौरान तिब्बती प्रदर्शनकारियों को परेशान किया

rfa.org, ०९. ०५. २०२४

चीन समर्थक कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान हंगरी के बुडापेस्ट में तिब्बती प्रदर्शनकारियों को परेशान किया। तिब्बती प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने एक बड़ा 'फ्री तिब्बत' बैनर को फाड़ दिया।

चीन समर्थक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों द्वारा लहराए गए तिब्बती झंडों को ओझल करने के लिए कम से कम १६ चीनी झंडे लहरा रखे थे और एक पुल पर लटके तिब्बती झंडे को रोक दिया, जिसके नीचे से शी के काफिले को स्वागत समारोह में जाना था।

तिब्बती समर्थकों ने कहा कि पास में खड़ी हंगरी की पुलिस ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

'स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत' के अभियान निदेशक चिमे ल्हामो ने सड़क पर पत्रकारों से कहा, 'ये लोग आए और हमारे बैनर फाड़ दिए और हंगरी पुलिस उन्हें अभी भी यहां रहने की अनुमति दे रही है, जिससे हमें और दूर धकेला जा रहा है। क्या यह एक स्वतंत्र देश है?'

एक कार्यकर्ता ने कहा कि सड़क पर संघर्ष के बाद प्रदर्शनकारियों का

पीछा बुडापेस्ट हवाई अड्डे की ओर जा रहे लगभग आठ अंडर कवर पुलिस अधिकारियों ने किया।
'इंटरनेशनल तिब्बत नेटवर्क' की तेनज़िन यांगज़ोम ने रेडियो फ्री एशिया को बताया, 'पिछले कुछ दिनों में हंगरी की अंडरकवर पुलिस और चीनी लोगों और शहर में हर जगह की पुलिस ने हमारा पीछा किया, हमें परेशान किया और धमकाया। शहर में हर जगह वे लोग हैं।'
उन्होंने कहा, 'हम तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, हांगकांग और उसके बाहर शी जिनपिंग की नरसंहार नीतियों और तिब्बतियों, हांगकांग वासियों, उइगरों और चीनी लोगों के साथ किए जा रहे व्यवहार का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए यहाँ आई हैं।'

◆ 15.एक्सक्लूसिव: मठ छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद किशोर तिब्बती भिक्षु ने आत्महत्या कर ली

rfa.org, २८. ०५. २०२४

सरकारी स्कूल में भेजे जाने के बाद १७ वर्षीय किशोर सदमे में आ गया था। २८. ०५. २०२४

तिब्बत के अंदर की आंखो देखी जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने रेडियो फ्री एशिया को बताया कि १७ वर्षीय तिब्बती बौद्ध भिक्षु को मठ छोड़ने और सरकारी स्कूल में नामांकन कराने के लिए मजबूर किए जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने स्कूल भेजकर उससे कहा था कि वह अब भिक्षुवाला कषाय चीवर धारण नहीं कर सकता है।

सुरक्षा कारणों से नाम उजागर न करने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि अप्रैल के मध्य में किंघई प्रांत के द्रक्कर काउंटी में कुंजांग लोंगयांग नामक भिक्षु की मौत हो गई।
भिक्षु की मौत ऐसे समय में हुई है जब युवा तिब्बती भिक्षुगण बौद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करने पर लगाए जा रहे कठोर प्रतिबंधों के कारण भारी दबाव का सामना कर रहे हैं।

इन प्रतिबंधों में २०१८ का एक आदेश भी शामिल है, जिसके अनुसार तिब्बती क्षेत्र के मठों से १८ वर्ष से कम उम्र के भिक्षुओं को बाहर कर दिया जाना है। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि किशोर भिक्षु अपने बारे में सोचने और निर्णय करने के मामले में बहुत अपरिपक्व हैं इसलिए उन्हें समाज की सेवा करनी चाहिए।

चीनी अधिकारी लंबे समय से तिब्बती सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का पारंपरिक रूप से केंद्र रहे तिब्बती बौद्ध मठों के आकार और प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं।

सूत्रों में से एक ने आरएफए को बताया, 'यहां तक कि सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी किशोर भिक्षुओं को स्कूल से अपने मठों में लौटने या यात्राओं पर जाने की अनुमति नहीं है।'

सूत्र ने कहा, 'सरकारी अधिकारी अपने खुफिया तंत्र के एजेंटों को यह निगरानी करने के लिए मठों में भेजते हैं कि क्या ये तिब्बती मठ किशोर आयु के भिक्षुओं को वापस बुला रहे हैं? तिब्बती मठों को यह धमकी भी दी जाती है कि अगर वे बच्चों को वापस बुलाते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।'

स्कूल में अवसादग्रस्त

तीनों सूत्रों ने आरएफए को बताया कि चीनी सरकार के अधिकारियों द्वारा तीन साल पहले १८ वर्ष से कम आयु के किशोरों को मठों से हटाने का नियम लागू करने के बाद लोंगयांग को ड्राकर काउंटी के युलुंग मठ से निष्कासित कर दिया गया था।
इसके बाद, लोंगयांग को एक स्थानीय स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें बताया गया कि वह भिक्षु की पोशाक यानि कषाय चीवर नहीं पहन सकते हैं। उन्हें कक्षा में उपस्थित रहने के दौरान सामान्य कपड़े पहनने होंगे।
स्रोत ने बताया कि स्कूल में वह गंभीर रूप से अवसादग्रस्त हो गए। उन्होंने खाना-पीना बंद कर दिया और कई दिनों तक बीमार पड़े रहे।

स्रोत ने बताया कि 'ऐसा कई बार हुआ और हर बार स्कूल के अधिकारियों ने उनके परिवार को उन्हें घर ले जाने के लिए बुलाया।'

शुरू में, स्कूल प्रशासकों ने कुछ सहूलियतें दी और उनके लिए नियमों में कुछ अपवाद रखे। तीनों सूत्रों ने बताया कि लोंगयांग को पूरे वर्ष स्कूल में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित परीक्षाओं और निरीक्षणों के लिए स्कूल में रहने के दौरान अपना चीवर धारण करने की अनुमति दी गई थी।

पह ये सारी सहूलियतें और नियमों में छूट कुछ महीने पहले समाप्त कर दिए गए। अब स्कूल के अधिकारियों ने फिर से आदेश दिया कि लोंगयांग और अन्य किशोर भिक्षुओं को चीवर छोड़कर स्थायी रूप से स्कूल में रहना होगा। सूत्रों ने बताया कि इससे लोंगयांग को बहुत परेशानी हुई।

अन्य सूत्रों में से एक ने कहा, 'लोंगयांग इस बात पर अड़ गए थे कि वह अपना भिक्षु वेष नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने हमेशा के लिए चीवर धारण करना छोड़ने के लिए और सामान्य वस्त्र पहनकर स्कूल जाने को मजबूर किया गया तो वह आत्महत्या कर लेंगे।' उनके द्वारा यह घोषणा किए जाने के कुछ ही दिन बाद वह फिर अवसाद में आ गए और इसके तुरंत बाद अप्रैल में लोंगयांग को फिर से स्कूल से घर भेज दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि उसी समय उन्होंने आत्महत्या कर ली।

◆ 16.फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से चीनी राष्ट्रपति शी के साथ बातचीत में तिब्बत का मुद्दा फ्रांसीसी रणनीति के केंद्र में रखने का आग्रह

tibet.net, ०६ मई, २०२४

ब्रुसेल्स। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिन की पेरिस यात्रा से पहले 'फ्रेंच पार्लियामेंटरी गुप फॉर तिब्बत' की अध्यक्ष फ्रांसीसी सीनेटर जैकलीन यूस्टेच-ब्रिनियो ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों को एक खुला पत्र लिखकर उनसे चीनी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान तिब्बत का मुद्दा उठाने का आग्रह किया।

१३ अन्य सीनेटरों के हस्ताक्षर वाले पत्र में सीनेटर यूस्टेच-ब्रिनियो ने चीनी राष्ट्रपति शी के शासन के तहत तिब्बत में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर प्रकाश डाला और तिब्बत के भू-राजनीतिक और पारिस्थितिकीय महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने आगे जोर दिया कि क्षेत्र में चल रहे अनेक संघर्षों के मद्देनजर तिब्बत मुद्दे के समाधान के लिए परम पावन दलाई लामा की पांच सूत्रीय शांति योजना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई लगती है।

सीनेटरों ने कहा, 'इसलिए, बातचीत की बहाली और तिब्बती लोगों के अधिकारों के प्रति सम्मान चीन के साथ बातचीत में फ्रांस की रणनीति के केंद्र में होना चाहिए।'

◆ 17.चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में तिब्बत में मानवाधिकारों के निरंतर उल्लंघन का जिक्र

tibet.net, १५ मई, २०२४

धर्मशाला। चीन को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के कार्यकारी आयोग (सीईसीसी) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के पैमाने पर वहां लगातार गंभीर उल्लंघनों को रेखांकित किया गया है। इसके प्रमाण के तौर पर तिब्बत की स्थिति को सामने रखा गया है, जहां तिब्बतियों को अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करने पर दंडित किया जाता है। इनमें धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति, पीआरसी नीतियों की आलोचना और ऑनलाइन सूचनाओं का आदान-प्रदान करना शामिल है। ०१ जुलाई २०२२ से ३० जून २०२३ तक की वार्षिक रिपोर्ट में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के शासन में मानवाधिकारों और कानून के शासन की गतिविधियों पर फोकस किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें २०१० से पीआरसी अधिकारियों और परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत बंद होने, पीआरसी के हस्तक्षेप और परम पावन दलाई लामा सहित तिब्बती बौद्ध लामाओं के पुनर्जन्म के चयन और मान्यता पर चीनी शासन द्वारा नियंत्रण किए जाने के प्रयासों पर नजर रखी गई है। इसके साथ इन नीतियों में आवासीय स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित करना शामिल है, जिनमें तिब्बती बच्चों को दाखिला लेने के लिए मजबूर किया जाता है।

रिपोर्ट में पीआरसी द्वारा तिब्बतियों के सामाजिक नियंत्रण, निगरानी और दमन के रूप में सुनियोजित तरीके से उनके डीएनए, रक्त के नमूने और आईरिस स्कैन संग्रह कार्यक्रमों की रूपरेखा दी गई है। इस रिपोर्ट में तिब्बती और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली पीआरसी की नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इन नीतियों में स्कूलों को बंद करना, मानक मंदारिन भाषा के अलावा किसी भी अन्य भाषा में शिक्षण पर प्रतिबंध लगाना, परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन को मनाने पर प्रतिबंध, ऐसे अवसरों के दौरान निगरानी बढ़ाना और परम पावन की तस्वीरें रखने या लेने-देने के खिलाफ शख्त चेतावनी देना शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि पीआरसी अधिकारी धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण आयोजनों और संवेदनशील तिथियों के आसपास। उदाहरणों में परम पावन दलाई लामा का जन्मदिन मनाने पर प्रतिबंध, ऐसे अवसरों पर निगरानी बढ़ाना और परम पावन की तस्वीरें साझा करने के खिलाफ चेतावनी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक हस्तियों के जन्मदिन मनाने वाले अनधिकृत सोशल मीडिया समूहों के लिए व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन को ऑनलाइन मनाने के खिलाफ चेतावनी दी गई है और विदेशों में दान भेजने के गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं, निर्वासित नेताओं का समर्थन करने के लिए भिक्षुओं को जेल की सजा मिली है। हिरासत में मौत और पुलिस यातना के आरोप जैसी दुखद घटनाएं तिब्बतियों के सामने दमनकारी माहौल को और उजागर करती हैं।

रिपोर्ट में तिब्बत में कोविड-१९ के प्रकोप के बाद सख्त 'जीरो कोविड' मानकों के प्रभाव को भी दर्शाया गया है, जिसके कारण लॉकडाउन के दौरान उचित सहायता न मिलने के कारण आलोचना और विरोध-प्रदर्शन हुए। अधिकारियों ने विरोध के स्वर को सेंसर किया, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया और तिब्बती बंदियों के साथ भेदभाव किया। प्रतिबंधों में आंशिक छूट के बावजूद, विरोध-प्रदर्शन जारी रहे। इन विरोध-प्रदर्शनों में खासकर हान चीनी प्रवासियों से तिब्बत छोड़ने को कहा गया, जो उनके बीच चल रहे तनाव को उजागर करते हैं।

२०२३ की वार्षिक रिपोर्ट में 'प्रौद्योगिकी-संवर्धित अधिनायकवाद' शीर्षक से एक नया अध्याय शामिल किया गया है। इसमें स्वीकार किया गया है कि कैसे उभरती हुई तकनीक चीन को और पूरी दुनिया को कहीं भी किसी की भी निगरानी, सेंसरशिप और स्वतंत्रता के दमन की सुविधा प्रदान करती है।

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए

सी.ई.सी.सी. की सिफारिशें:

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों को निम्नलिखित कार्यवाहियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

- संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करें ताकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारियों को चीन अधिकृत तिब्बती क्षेत्रों में यात्रा करने की व्यवस्था करने में मदद मिल सके। बिना बाधा की तिब्बत यात्रा में ये अधिकारी स्वतंत्र रूप से वहाँ मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन कर सकेंगे। इस दौरे में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिबंध या बाधा नहीं होगा। इस आकलन के बाद उनके निष्कर्षों पर संयुक्त राष्ट्र को एक पूरी रिपोर्ट दी जा सकेगी। चीन अधिकृत तिब्बती क्षेत्रों में यात्रा करने को उत्सुक संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों में मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, अल्पसंख्यक मुद्दों पर विशेष प्रतिवेदक और शिक्षा के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक शामिल हैं।

- तिब्बत में बड़े पैमाने पर जबरदस्ती बायोमेट्रिक डेटा-एकत्रीकरण और निगरानी कार्यक्रमों सहित घोर मानवाधिकार उल्लंघनों में लिप्त चीनी पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन अनैतिक कार्यों में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों की बिक्री या अनुदान देने वाली अमेरिकी कंपनियों को ऐसा करने से रोकने के लिए उचित कानून पारित करें और लागू करें। चीनी पुलिस और कानून पर्वतन एजेंसियों के संपर्क में रहने वाली अमेरिकी कंपनियां चीनी बलों को ऐसे उपकरण धड़ल्ले से बेच रही हैं।

- समान विचारधारा वाले देशों में सरकारी अधिकारियों, सांसदों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस बात के लिए काम करें कि चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर तिब्बतियों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने के लिए दबाव बनाया जा सके। चीनी सरकार को यह मानने के लिए मजबूर किया जा सके कि चीन के संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत तिब्बतियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों का पालन करने का अधिकार है। इन कानूनों के तहत भी तिब्बती बौद्धों को यह अधिकार मिला हुआ है कि वे दलाई लामा सहित सभी लामाओं के पुनर्जन्म की पहचान करें और उन्हें तिब्बती बौद्ध रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप तरीके से शिक्षित-प्रशिक्षित करें।

- चीनी सरकार से आगह करें कि वह दलाई लामा को चीन की सुरक्षा के लिए खतरा मानना बंद करे और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के वास्तविक बातचीत को फिर से शुरू करे।

- अपने मानवाधिकारों का शांतिपूर्ण उपयोग करने के कारण वर्तमान में हिरासत में लिए गए या कैद किए गए तिब्बती राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आह्वान चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत में करें। आयोग के राजनीतिक कैदी डेटाबेस में हिरासत में लिए गए तिब्बतियों के आंकड़े इस तरह की वकालत के लिए उपयोगी संसाधन हो सकते हैं। चीनी सरकार और उसकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा चीनी सुरक्षा बलों से आग्रह करें कि वे तिब्बतियों को अपने मानवाधिकारों के शांतिपूर्ण उपयोग करने दें। उन्हें इन अधिकारों के उपयोग से रोकने के लिए दबाने, दंडित करने, मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, गायब करने, उनके साथ मारपीट करने, उन्हें यातना देने और उन्हें डराने-धमकाने से बाज आएं।

- चीनी सरकार से आग्रह करें कि वह दुनिया भर की सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा से मिलने के लिए आमंत्रित करें। गेधुन चोएक्यी न्यिमा को दलाई लामा ने ११वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन मान्यता के तुरंत बाद ११वें पंचेन लामा और उनके माता-पिता को १९९५ में अपहरण कर लिया गया था।

18.तिब्बत के १४वें दलाई लामा होने के मायने

tibet.net, २० मई, २०२४

मोहन गुरुस्वामी, डेक्कन क्रॉनिकल

१४वें दलाई लामा (आध्यात्मिक नाम: जेट्सन जम्पेल न्गवांग लोबसंग येशे तेनजिन ग्यात्सो) का जन्म ०६ जुलाई, १९३५ को हुआ था। परम पावन १९५९ से भारत में रह रहे हैं और वे तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और सबसे सम्मानित प्रमुख हैं। जब मैं तिब्बत गया था तो आम तिब्बतियों को उनके द्वारा धारण किया जानेवाले परंपरागत पदक को बड़े ही आदर-भाव से पहने हुए देखना आम बात थी। तिब्बत, युन्नान और किंघई प्रांतों में ज़्यादातर तिब्बतियों की दुकानों में उनकी तस्वीरें देखना भी बहुत आम बात थी। दलाई लामा का धार्मिक प्रभाव भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे सीमावर्ती प्रदेशों और और लद्दाख जैसे केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

चीन के साथ ऐतिहासिक-राजनीतिक पहचान के बावजूद तिब्बत ने पारंपरिक रूप से नैतिक और आध्यात्मिक पोषण के लिए भारत का ही मुंह देखा है। तिब्बत का चीन के साथ संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। इसका प्रमाण है कि वर्तमान १४वें दलाई लामा भारत में शरण लेने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। भारत और चीन के बीच स्वतंत्र तिब्बत को बफर स्टेट बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक सक्रिय नीति अपनाई थी। ल्हासा में चीनी अम्बान (पूर्णाधिकारी) ने तिब्बत में यंग हसबैंड के अभियान के प्रयासों को बड़े शांत दिमाग से देखा और इसका तत्कालिक परिणाम तिब्बत की स्वतंत्रता पर चीनी हमले के रूप में निकला था। ०१ जनवरी, १९१२ को चीनी गणराज्य की स्थापना और डॉ. शनयात सेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उस वर्ष अप्रैल में १३वें दलाई लामा ने चीन के साथ तिब्बत के संबंधों के अंत की घोषणा कर दी और अम्बान और सभी चीनी सैनिकों को तिब्बत से निष्कासित कर दिया। १९४९ में गृहयुद्ध में जीत के लगभग तुरंत बाद चीनी कम्युनिस्टों ने तिब्बत पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस बीच के दौर के लगभग चार दशकों से अधिक समय तक तिब्बत स्वतंत्र रहने का स्वाद ले रहा था।

इसके बाद से भारत ने तिब्बत को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा स्वीकार करके तिब्बत समस्या से मुंह मोड़ लेने का प्रयास किया है। बाद के वर्षों में चीनी कम्युनिस्टों ने माओ के नेतृत्व में तिब्बती राष्ट्रवाद और वहां के बौद्ध धर्म का सफाया करने का प्रयास करके तिब्बत समस्या

को हल करने की कोशिश की। यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद चीन ने तिब्बत के धर्म और संस्कृति का चीनी-हान मूल में धीरे-धीरे विलय कर देने की नीति अपनाई और इसके साथ ही तिब्बत में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास शुरू किया। यह नीति भी चीनियों के लिए आंशिक रूप से ही कारगर साबित हो रही हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि माओवादी लौह शिकंजे की तुलना में इस नीति से वे बेहतर कर पाए हैं।

हालांकि तिब्बत अब अपेक्षाकृत निष्क्रिय मुद्दा हो चुका है, लेकिन यह अभी भी एक बारूद का ढेर बना हुआ है और चीनी की किसी भी चिंगारी से यहां आग भड़कने की आशंका है, जिससे चीन डरता है। भारत के लिए भी नीति आंशिक रूप से ही कारगर रही है। अब १,५०,००० से अधिक तिब्बती शरणार्थी भारत में रहते हैं और भारत अनजाने में तिब्बतियों द्वारा अपने राष्ट्र को पुनः प्राप्त करने के विश्वव्यापी संघर्ष का केंद्र बन चुका है। संक्षेप में, तिब्बत मुद्दा हालांकि अब निष्क्रिय है, लेकिन अभी भी बहुत जीवंत है और भारत इसे पसंद करे या न करे, तिब्बत का खेल उसके आंगन में खेला जा रहा है।

परम पावन दलाई लामा और उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान इस सतत संघर्ष के केंद्र में है। परम पावन आज की दुनिया में कई आदर्शों और छवियों के प्रतीक बन गए हैं। नए युग के अध्यात्मवाद, नैतिकता, पारिस्थितिकीय मूल्यों और राजनीति के मिश्रण ने दलाई लामा को तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रतीक बना दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम के कई प्रभावशाली और धनी हस्तियों को बौद्ध धर्म का अनुयायी और तिब्बत मुद्दे का समर्थक बना लिया है। आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के एक उपनगर मैक्लोडगंज का छोटा सा इलाका परम पावन दलाई लामा के आवास के कारण आकर्षक का केंद्र बन गया है। मैक्लोडगंज आज बड़ी संख्या में पश्चिम के उन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जो जीवन का नया अर्थ और उद्देश्य तलाशने के लिए व्यग्र हैं। मैक्लोडगंज अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जैसी शीर्ष राजनीतिक हस्तियों से लेकर रिचर्ड गेरे और उमा थुरमन जैसे शीर्ष हॉलीवुड अभिनेताओं तक को आकर्षित करता है। इन परिस्थितियों में चीन और भारत दोनों को दलाई लामा के बाद के हालात के बारे में चिंता करनी चाहिए। तिब्बती दलाई लामा को अपना धरती पर का ईश्वर मानते हैं। लेकिन वह भी इंसान हैं और उन्हें सभी इंसानों की तरह एक दिन दुनिया से विदा होना होगा। वह अब ८८ वर्ष के हो चुके हैं और समय निश्चित रूप से उनके पक्ष में नहीं है। जब तक वे इस दुनिया में हैं, वे तिब्बती राष्ट्रवाद की चिंगारी को नए युग के बौद्ध धर्म के उस कंबल को सुलगाने से रोकते हैं, जिसे उन्होंने खुद बुना है। जब परम पावन दलाई लामा नहीं रहेंगे तब चिंगारी धधक सकती है। निर्वासित तिब्बतियों द्वारा खोजे गए दलाई लामा को चुनौती मिलना अवश्यंभावी है। चीनी कम्युनिस्ट निश्चित तौर पर अपने स्वयं का दलाई लामा पेश कर उनको अवतार के तौर पर थोपने की कोशिश करेंगे और इसे वैध बनाने की येन-केन-प्रकारेण कोशिश में अपने सारे घोड़े एक साथ खोल देंगे। हालांकि इस काम में उनकी सफलता असंभव है, लेकिन यह निश्चित रूप से स्थिति को असमंजस में डाल देगा और भविष्य में तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक नेतृत्व के मुद्दे पर किसी भी समझौते को समाप्त कर देगा। अगर एक बार आध्यात्मिक नेतृत्व को लेकर विवाद खड़ा हो गया तो यह भी ध्रुव सत्य है कि निर्वासित तिब्बतियों की नई पीढ़ी तिब्बती राष्ट्रवादी आंदोलन पर उतारू हो जाएगी और अपना नया राजनीतिक नेतृत्व खोज लेगी। यदि भारत में खोजे गए दलाई लामा के अगले अवतार का आसपास के शासन द्वारा विरोध किया जाता है, तो हम लगभग निश्चित रूप से युवा तिब्बतियों के दिलों और दिमागों में भयंकर उथल-पुथल देखेंगे। इससे अनिवार्य रूप से तिब्बतियों का अधिक मुखर रुख सामने आएगा क्योंकि विभिन्न गुट सत्ता के लिए होड़ में शामिल हो जाएंगे। इस तरह के आंतरिक संघर्षों के परिणामस्वरूप उग्रवाद का बढ़ना लाजिमी है, जिसका आधार भारत में बनना तय है। दूसरी ओर, हम निर्वासित तिब्बतियों के बीच नेतृत्व की दोहरी छवि उभरती हुई देख सकते हैं। एक आध्यात्मिक नेतृत्व जो संसार से विमुख होकर निवृत्तिगामी हो सकता है जबकि दूसरा उग्रवादी नेतृत्व जो राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष का नेतृत्व करनेवाला होगा। यह दलाई लामा की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का परिणाम है कि इस तरह के दोहरे नेतृत्व की रूपरेखा अब उभर रही है, जिसमें दूसरे सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु उगेन थिनले, करमापा (अब जर्मनी में) और निर्वासित सरकार के सिक्योंग (अध्यक्ष) पेन्पा शेरिंग शामिल हैं। दोनों अब निर्वासित तिब्बती समूहों के बीच और तिब्बत के भीतर के तिब्बतियों में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। भारतीय दृष्टिकोण से इन दोनों के बीच का वैकल्पिक धार्मिक नेतृत्व का उदय तिब्बती बौद्ध आंदोलन के विखंडन को रोक सकता है। युवा करमापा इसे अच्छी तरह से संभाल कर सकते हैं। भौगोलिक और जातीय रूप से लद्दाख का अधिकांश भाग तिब्बती चांगथांग का विस्तार है और वहां बोली जाने वाली मुख्य भाषा तिब्बती की ही एक बोली है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र १९५० के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा कब्जा किए जाने तक ल्हासा में दलाई लामा के अस्थायी नियंत्रण में था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन के साथ सीमा विवाद वास्तव में तिब्बत के साथ सीमा विवाद है। यह अलग बात है कि अगर तिब्बत वास्तव में स्वतंत्र होता तो वह चीनियों की तरह अपने दावों को पुख्ता नहीं कर पाता। 'तवांग और आसपास के क्षेत्रों' पर चीन का दावा काफी हद तक वर्तमान दलाई लामा द्वारा १९४० के दशक के अंत में किए गए दावे पर आधारित है। उस समय उन्होंने नव स्वतंत्र भारत की सरकार को एक पत्र लिखकर इस पर औपचारिक दावा किया था। अब से दो दशक बाद चीन एक बूढ़ा राष्ट्र होगा और इसलिए उसे लगता है कि उसे वर्तमान अवसर का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। भारत के खिलाफ उसकी समय-समय पर होने वाली आक्रामकता का संबंध जमीन के टुकड़े से कहीं अधिक इसी मुद्दे से है। कुल मिलाकर तिब्बती नेतृत्व में परिवर्तन एक प्रमुख विचारणीय बिंदु है।

◆ 19.अमेरिकी आयोग ने चीन द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म तेज 'चीनीकरण' पर प्रकाश डाला

savetibet.org, ०२ मई, २०२४

'अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूनाईटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम- यूएससीआईआरएफ)' की ०१ मई को प्रकाशित २०२४ की वार्षिक रिपोर्ट में चीनी सरकार द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के बर्बर दमन और उसका 'चीनीकरण' किए जाने के कारण तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है। चीनीकरण एक चीनी नीति है जिसका उद्देश्य तिब्बती बौद्ध धर्म को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरूप बनाकर उसके नियंत्रण में लाना है।

चीन को 'विशेष चिंता' वाले देश की श्रेणी में रखें

२०२४ की वार्षिक रिपोर्ट के वर्चुअल लॉन्च के दौरान यूएससीआईआरएफ की ओर से बोलते हुए आयोग के उपाध्यक्ष फ्रेडरिक ए. डेवी ने अमेरिकी विदेश विभाग से सिफारिश की कि वह धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के दोषी चीन को 'विशेष चिंता का विषय वाले देश (सीपीसी)' की श्रेणी वाले

१७ देशों में से एक के रूप में नामित करे।

आयोग के मुख्य निष्कर्षों से पता चलता है कि तिब्बती बौद्धों पर निगरानी और सुरक्षा उपायों में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी शांतिपूर्ण धार्मिक गतिविधियों पर अनेक प्रतिबंध लग गए हैं। इसमें कहा गया है कि शांतिपूर्ण धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने या परम पावन दलाई लामा से संबंधित सामग्री रखने के आरोप में तिब्बती बौद्धों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। कुछ को आत्मदाह करने से रोकने के नाम पर 'राजनीतिक पुनःशिक्षा शिविरों' में भेजा गया है, जहां तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु हो गई है।

एक ऑनलाइन डेटाबेस के अनुसार आयोग की धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का उपयोग करने के कारण बने पीड़ितों की सूची में ९३ तिब्बती शामिल हैं।

तिब्बती बच्चों का जबरन नस्लीय विलय

सरकारी आवासीय स्कूलों में १० लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग करने और तिब्बतियों को बौद्ध धर्म का स्वेच्छा से पालन करने से रोकने के लिए सरकार के उपायों पर प्रकाश डालते हुए आयोग कहता है, 'सरकार ने १० लाख तिब्बती बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया, उन्हें जबरन अपने नस्ल में विलय करने के लिए सरकारी आवासीय स्कूलों में डाल दिया। कुछ स्थानीय अधिकारियों ने माता-पिता को तिब्बती बच्चों को धर्म की शिक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया। सरकार ने तिब्बती भिक्षुओं की नियुक्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और दलाई लामा के पुनर्जन्म में हस्तक्षेप करने और उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के अपने इरादे को दोहराया।

मानवाधिकार प्रतिबंध

आयुक्त सूसी जेलमैन ने आयोग की भूमिका और अमेरिकी सरकार द्वारा २०२३ में लक्षित मानवाधिकार प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर जोर दिया, जिसमें चीनी अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने बिडेन प्रशासन द्वारा उन चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का हवाला दिया 'जो तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग करते हैं और तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करना चाहते हैं।'

धर्म का चीनीकरण

आयोग धार्मिक स्वतंत्रता में गिरावट के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में चीनी सरकार की बहुआयामी 'बौद्ध धर्म के चीनीकरण' नीति को जिम्मेदार ठहराता है। इस नीति के तहत सभी प्रमुख धार्मिक समूहों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और उसकी नीतियों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है।

आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि 'चीनीकरण के लिए धार्मिक समूहों को अपने धर्म की सीसीपी द्वारा की गई मार्क्सवादी व्याख्या का पालन करना आवश्यक है, जिसमें उस व्याख्या के अनुरूप धार्मिक शास्त्रों और सिद्धांतों को बदलना भी शामिल है।' तिब्बत में चीनी सरकार की 'धर्म के चीनीकरण' नीति के प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने कहा कि 'चीनीकरण नीति के तहत तिब्बत की स्थानीय आबादी को चीनी व्याख्या के तहत उसमें जबरन आत्मसात कर लेना शामिल है, जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को खतरा उत्पन्न हो गया है।'

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Acting Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः coordinator@indiatibet.net

हंगरी के बुडापेस्ट में गेलर्ट हिल पर तिब्बती झंडे के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा का विरोध करते समय हंगरी पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर आक्रोश में चिल्लाता हुआ तिब्बती प्रदर्शनकारी।

सभा में मौजूद भारत-तिब्बत सहयोग मंच के सदस्य और तिब्बती स्थानीय समुदाय।

अमेरिकी आयोग ने चीन द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म तेज 'चीनीकरण' पर प्रकाश डाला